

तेल क्षेत्र संशोधन अधियक 2024

प्रलिस के लयः

राजसभा, हाइड्रोकारबन, हीलयम, कच्चा तेल और प्राकृतक गैस, पेट्रोलयम और प्राकृतक गैस बोर्ड वनियामक बोर्ड

मेन्स के लयः

तेल क्षेत्र (वनियमन और वकिस) संशोधन अधियक 2024, खनजि तेल नषिकरण में वनियमन, भारत की ऊरजा नीतयिँ।

[स्रोत: इंडयन एक्सप्रेस](#)

चरचा में क्योँ?

हाल ही में तेल क्षेत्र (वनियमन और वकिस) संशोधन अधियक, 2024 को [राजसभा](#) द्वारा पारति कयिा गया, जसिका उद्देश्य नज़ी नवश को आकर्षति करते हुए पेट्रोलयम एवं खनजि तेलों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहति करना है।

- इस अधियक का उद्देश्य तेल उत्पादन के प्रशासन को खनन गतवधियिँ से स्पष्ट रूप से अलग करके मौजूदा तेल क्षेत्र अधनियम 1948 में संशोधन करना है।

तेल क्षेत्र संशोधन अधियक के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- खनजि तेल की परभाषा:** अधियक खनजि तेलों की परभाषा को व्यापक बनाता है, जसमें प्राकृतक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोकारबन (जैसे पेट्रोलयम और प्राकृतक गैस) के साथ-साथ कोल बेड मीथेन और शेल गैस/तेल को भी शामिल कयिा गया है।
 - इस परभाषा में कोयला, [लगनाइट](#) और [हीलयम](#) को वशिष रूप से शामिल नहीं कयिा गया है, संभवतः इसका कारण खान और खनजि (वकिस और वनियमन) अधनियम, 1957 के तहत उनका वनियमन है।
- पेट्रोलयम लीज़:** अधियक “माइनगि लीज़” शब्द के स्थान पर “पेट्रोलयम लीज़” शब्द का प्रयोग करता है, जो खनजि तेलों की खोज, उत्पादन और नपिटान जैसी गतवधियिँ को नयितरति करेगा।
 - तेल क्षेत्र अधनियम, 1948 के तहत दयि गए मौजूदा माइनगि लीज़/खनन पट्टे वैध रहेंगे और उनमें कोई परविरतन नहीं कयिा जाएगा।
- उल्लंघन के लयि दंड:** तेल क्षेत्र अधनियम, 1948 के तहत उल्लंघन के परणामस्वरूप छह माह तक का कारावास, 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- नवीन अधियक तेल क्षेत्र अधनियम के उल्लंघन हेतु आपराधक दंड के स्थान पर वतृतीय दंड का प्रावधान करता है, जससे अधिकतम जुर्माना राशा 25 लाख रुपए हो जाती है, तथा नरंतर उल्लंघन के लयि 10 लाख रुपए तक का अतरिकित दैनक जुर्माना भी लगाया जाता है।**
- नज़ी नवश को प्रोत्साहन:** अधियक में पेट्रोलयम उत्पादन में नज़ी नवश को आकर्षति करने के उपाय शामिल हैं, तथा यह स्पष्ट कयिा गया है कऱि मौजूदा खनन पट्टे, पट्टेधारकों को कऱी प्रकार का नुकसान पहुँचाए बगैर वैध बने रहेंगे।
- केंद्र सरकार की नयिम बनाने की शक्तयिँ:** अधियक में केंद्र सरकार को वभिन्न पहलुओं पर नयिम बनाने की शक्ति बरकरार रखी गई है, जसमें पट्टे प्रदान करना और उनका वनियमन करना, नयिम और शर्तें नरिधारति करना (जैसे पट्टे का क्षेत्र और अवधि), खनजि तेलों का संरक्षण और वकिस, तथा रॉयल्टी के संग्रह के साथ-साथ तेल उत्पादन के तरीके शामिल हैं।
- इसके अलावा, अधियक केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर पेट्रोलयम पट्टों का समेकन, सुवधि साझाकरण, प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को संरक्षति करने के लयि पट्टाधारकों की ज़मिंदारयिँ, तथा पेट्रोलयम पट्टा पुरस्कारों के लयि वैकल्पक वविवद समाधान प्रकरयिँ शामिल करता है।**
- दंड का नरिणय:** केंद्र सरकार दंड का नरिणय करने के लयि संयुक्त सचवि स्तर या उससे उच्च स्तर के अधिकारि की नयुक्ति करेगी।
 - न्यायनरिणायक प्राधिकरण के नरिणयों के वरिद्ध अपील [पेट्रोलयम एवं प्राकृतक गैस बोर्ड वनियामक बोर्ड \(PNGRB\) अधनियम, 2006](#) में नरिदषिट अपीलय न्यायाधकिरण में की जाएगी।
 - PNGRB अधनियम, 2006 के अनुसार, PNGRB के नरिणयों के वरिद्ध अपील वदियुत अपीलय न्यायाधकिरण के समक्ष की जानी है, जसिका गठन [वदियुत अधनियम, 2003](#) के अंतर्गत कयिा गया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बोर्ड नियामक बोर्ड

- PNGRB की स्थापना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस वनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के तहत की गई थी।
- नोडल मंत्रालय: [पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय](#)
- इसका उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना, पेट्रोलियम से संबंधित गतिविधियों को वनियामित करना और प्रतस्पर्द्धी बाजारों को बढ़ावा देना है।
- PNGRB [सिटी गैस वितरण \(CJD\) नेटवर्क](#), प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को अधिकृत, टैरिफ का निर्धारण तथा तकनीकी एवं सुरक्षा मानक स्थापित करता है।

तेल क्षेत्र संशोधन विधियक, 2024 के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं?

- **राज्य के अधिकारों पर प्रभाव:** विधियक में खनन पट्टों से पेट्रोलियम पट्टों की ओर बदलाव से राज्य सूची की प्रवर्षिटा 50 के अंतर्गत आने वाले राज्य के कराधान अधिकारों का हनन हो सकता है।
 - [2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय](#) के फैसले ने पुष्टि की कि राज्यों को भारतीय संविधान में [राज्य सूची की प्रवर्षिटा 50](#) के तहत खनन गतिविधियों पर कर लगाने का विशेष अधिकार है।
 - आलोचकों का तर्क है कि [संघ सूची की प्रवर्षिटा 53](#), जो केंद्र सरकार को तेल क्षेत्रों और खनन तेलों पर अधिकार प्रदान करती है, केंद्रीय नियंत्रण को बढ़ा सकती है, जिससे संघवाद से संबंधित चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं तथा अधिकार क्षेत्र एवं राजस्व पर संभावित विवाद देखने को मलि सकते हैं।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:** नजि खलिाइयों की बढ़ती भागीदारी से पर्यावरण संबंधी सुरक्षा उपाय कमजोर हो सकते हैं।
 - ऐसी आशंका है कि नजि कंपनियों [पर्यावरण संरक्षण की अपेक्षा मुनाफे को प्राथमिकता देगी](#), जिससे उत्सर्जन और पारस्थितिकी कर्षता बढ़ सकती है।
- **गैर-अनुपालन के लिये दंड:** आपराधिक दंड के स्थान पर जुर्माने लगाने से जवाबदेही संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होंगी, जिससे संभावित रूप से नविरण और सुरक्षा एवं पर्यावरण मानकों के अनुपालन में कमी आएगी।
- **नजि नविश बनाम सार्वजनिक क्षेत्र की प्राथमिकता:** [वपिकषी दलों का तर्क है कि संसाधन अन्वेषण के लिये तेल और प्राकृतिक गैस नगिम \(ONGC\)](#) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को नजि संस्थाओं की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
 - आलोचकों को डर है कि नजि नविश से सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व कमजोर हो सकता है और [सांसाधनिक कल्याण तथा स्थिरता की तुलना में लाभ को प्राथमिकता दी जा सकती है](#)।

आगे की राह

- **क्षेत्राधिकार संबंधी सीमाएँ:** क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों को रोकने के लिये केंद्रीय एवं राज्य प्राधिकरण के बीच स्पष्ट सीमाएँ स्थापित करने के साथ संसाधन प्रशासन में सहकारी संघीय संरचना सुनिश्चित करना आवश्यक है।
 - **पारदर्शी राजस्व साझाकरण:** संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करने और वित्तीय नियंत्रण पर तनाव कम करने के लिये [केंद्र एवं राज्यों के बीच पारदर्शी तथा न्यायसंगत राजस्व-साझाकरण तंत्र](#) विकसित करना चाहिये।
 - **धारणीय प्रथाएँ:** उन कंपनियों को प्रोत्साहन देना चाहिये जो धारणीय प्रथाओं को प्राथमिकता (जैसे कि [कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में नविश करने के लिये कर छूट या कम रॉयल्टी लेना](#)) देती हैं।
- **पर्यावरण नियमों को मजबूत करना:** विधियक के अंतर्गत [मजबूत पर्यावरण सुरक्षा उपायों](#) को लागू करने से तेल उत्पादन में नजि क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी से संबंधित जोखिमों को कम कथि जा सकता है। इसमें नई परियोजनाओं के लिये [अनविार्य पर्यावरण प्रभाव आकलन](#) शामिल है।
- **जन जागरूकता अभियान:** घरेलू तेल उत्पादन के लाभों एवं ऊर्जा सुरक्षा पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने से विधियक के प्रति जन समर्थन को बढ़ावा मलिगा तथा इससे संबंधित नकारात्मक धारणाओं को भी दूर कथि जा सकेगा।

दृष्टिभेन्स प्रश्न

प्रश्न: भारत की ऊर्जा सुरक्षा एवं राज्य के अधिकारों पर तेल क्षेत्र (वनियमन और विकास) संशोधन विधियक, 2024 के नहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष प्रश्न

प्रश्न: कभी-कभी समाचारों में पाया जाने वाला शब्द 'वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट' नमिनलखिति में से कसि संदर्भित करता है: (2020)

- कच्चा तेल
- बहुमूल्य धातु
- दुर्लभ मृदा तत्त्व
- यूरेनियम

उत्तर: (a)

प्रश्न. जैव ईंधन पर भारत की राष्ट्रीय नीति के अनुसार, जैव ईंधन के उत्पादन के लिये नमिनलखिति में से कसिका उपयोग कच्चे माल के रूप में कथिया जा सकता है? (2020)

1. कसावा
2. कषतगिरस्त गेहूँ के दाने
3. मूँगफली के बीज
4. चने की दाल
5. सड़े हुए आलू
6. मीठे चुकंदर

नीचे दथि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनथि:

- (a) केवल 1, 2, 5 और 6
- (b) केवल 1, 3, 4 और 6
- (c) केवल 2, 3, 4 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

उत्तर: (a)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/oilfields-amendment-bill-2024>

